

भारत सरकार  
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न सं. 2901**  
06.08.2025 को उत्तर देने के लिए

आंकड़ा संग्रहण प्रणाली का आधुनिकीकरण

2901. श्री छोटेलाल:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार रोजगार, बेरोजगारी, गरीबी और आय असमानता पर सांख्यिकीय आंकड़ों की सटीकता और सुसंगतता से संबंधित चुनौतियों से अवगत है, जो साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण और लक्षित कल्याण कार्यक्रमों के लिए आवश्यक हैं; और
- (ख) यदि हां, तो आंकड़ा संग्रहण प्रणाली को मजबूत और आधुनिक बनाने, सर्वेक्षण पद्धतियों में सुधार करने, रिपोर्टों का नियमित और पारदर्शी प्रकाशन सुनिश्चित करने, राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाने और रोजगार और गरीबी पर अधिक विश्वसनीय और वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान अपनाने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित पहलों और नीतिगत उपायों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) और (ख): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा.) देश में सांख्यिकीय प्रणाली के नियोजित विकास के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते, डेटा गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने हेतु भी उत्तरदायी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सर्वेक्षणों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का उपयोग विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों आदि द्वारा भारत में विभिन्न प्रमुख संकेतकों के आधिकारिक डेटा स्रोत के रूप में किया जाता है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) देश में रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित विभिन्न संकेतकों का अनुमान लगाने के लिए वर्ष 2017 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) आयोजित कर रहा है। पीएलएफएस के संवर्धित कवरेज के साथ उच्च आवृत्ति श्रम बाजार संकेतकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जनवरी 2025 से पीएलएफएस के प्रतिदर्श डिजाइन को नया रूप दिया गया है।

आय असमानता से संबंधित आंकड़े केन्द्र सरकार द्वारा संकलित नहीं किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग को बहुआयामी गरीबी अनुमानों को मापने के लिए एक स्वदेशी सूचकांक तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

एनएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय देश भर में किए जाने वाले बड़े पैमाने के सर्वेक्षणों में सटीक, विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाले आंकड़े सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे प्राप्त करने के लिए, विभिन्न सांख्यिकीय उत्पादों में सुदृढ़ और सुपरिभाषित तंत्रों का उपयोग किया जाता है, जिनमें उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उभरती आवश्यकताओं, फीडबैक और कार्यप्रणाली में प्रगति के आधार पर समय-समय पर सुधार किए जाते हैं। मौजूदा आईटी आधारित डेटा संग्रहण तकनीकों का उन्नयन और समन्वयन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में एक सतत प्रक्रिया है। सभी सर्वेक्षणों में प्राथमिक डेटा संग्रहण, कंप्यूटर सहायता प्राप्त व्यक्तिगत साक्षात्कार (सीएपीआई) या वेब-आधारित एप्लिकेशन का उपयोग करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है, जिसमें डेटा संग्रहण के चरण में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित सत्यापन तंत्र भी शामिल है। इससे सर्वेक्षण डेटा को वास्तविक समय पर प्रस्तुत करने और सत्यापित करने में सुविधा होती है और इसके परिणामस्वरूप सर्वेक्षण रिपोर्टें जारी करने में लगने वाले समय में भारी कमी आई है। इसके अतिरिक्त, जब भी कोई नया सर्वेक्षण शुरू किया जाता है, तो उनके उचित रूप को अपनाने के लिए संभावित तरीकों और नई प्रौद्योगिकियों की खोज की जाती है। उदाहरण के लिए, एआई/एमएल की कुछ विशेषताएं उद्यम सर्वेक्षणों जैसे कैपेक्स और वार्षिक असंगठित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण (एसयूएसई) में शामिल की गई हैं, सीएपीआई को एसयूएसई, पीएलएफएस आदि जैसे चल रहे सर्वेक्षणों में सक्रिय बनाया गया है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तकनीकी मार्गदर्शन, प्रतिदर्श डिजाइन, सर्वेक्षण उपकरण और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सांख्यिकी तैयार करने में सहायता करता है, जिसमें प्रशिक्षण और टैबलेट, सीएपीआई और क्लाउड सर्वर जैसी डिजिटल अवसंरचना शामिल हैं। राज्यों को डेटा की गुणवत्ता और आउटपुट की जांच के लिए स्थानीय विशेषज्ञों के साथ तकनीकी समितियां बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

सर्वेक्षण आंकड़ों में पारदर्शिता और समयबद्धता बढ़ाने के लिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अग्रिम रिलीज कैलेंडर में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार सर्वेक्षण परिणामों की रिपोर्टें इकाई स्तर के आंकड़ों के साथ इस मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी की जाती हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संशोधित माइक्रो-डेटा पोर्टल, जीओआई स्टैट्स (GoIStats) मोबाइल ऐप और ई-सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, जो सामयिक और मूल्यवान डेटा इनपुट प्रदान करने के उद्देश्य से देश भर में आधिकारिक आंकड़ों के आसान प्रसार की सुविधा प्रदान करते हैं।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सर्वेक्षणों के विषय, परिणाम, कार्यप्रणाली, प्रश्नावली आदि पर समय-समय पर उठाए गए मुद्दों के समाधान तथा रूपरेखा की समीक्षा के उद्देश्य से समिति/कार्य समूह गठित किए गए हैं, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, शिक्षा, अनुसंधान, अर्थशास्त्र, वित्त आदि से विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं।

\*\*\*\*\*